

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा— प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अगले 6 महीने में और कड़े फैसले लेगी सरकार।
- राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा— राज्य में डैम सेफ्टी एक्ट को कड़ाई से किया जाएगा लागू।
- विपक्षी दल भाजपा ने प्रदेश के वित्तीय हालात और विधानसभा अध्यक्ष के रवैये को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन।
- पैरिस पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में ऊना के निषाद कुमार ने जीता रजत पदक— राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री व उप-मुख्यमंत्री ने दी बधाई।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार अगले 6 महीने में और कड़े फैसले लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले बजट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता नजर आएगा। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी एक सौ 25 यूनिट फ्री बिजली को वापस नहीं लिया है। मुख्यमंत्री ने पूर्व की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने पिछले पांच सालों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अब राज्य सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के पहले दिन से ही प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन लोगों को सब्सिडी पर बिजली की जरूरत नहीं है उन्हें भी सब्सिडी दी गई है और राज्य सरकार ने पहली सितंबर से उद्यमियों या फाइव स्टार होटल मालिकों को प्रति यूनिट एक रुपए सब्सिडी को विद-ड्रॉ कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह फैसला बिजली बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सही ढंग से काम करेगी और 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो सरकार को सब्सिडी के तौर पर बिजली बोर्ड को 2 हजार 2 सौ करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि विपक्षी दल भाजपा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना सहयोग दे, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। विधायक विवेक शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि खैर का कटान उसकी मोटाई के हिसाब से होता है। उन्होंने कहा कि खैर को जड़ से न काटा जाए, इस पर विचार किया जाएगा। विधायक अनुराधा राणा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जल्द ही 6 सौ भर्तियां विभिन्न श्रेणियों में की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ भेजा जा रहा है और इनमें स्टाफ की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विभाग में 2 सौ डाक्टरों की भर्ती का मामला लोक सेवा आयोग को भेजा गया है जिन्हें जल्द भरा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर फोकस कर रही है, जिसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल के जवाब में बताया कि प्रदेश के स्कूलों में 6 साल के बच्चे को ही पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा और भविष्य में इस नियम में किसी को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि नेशनल एजूकेशन पॉलिसी में यह प्रावधान है और पिछले साल से हिमाचल सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है। राजस्व विभाग द्वारा करवाए गए बंदोबस्त को लेकर कई क्षेत्रों में विवाद है, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड उर्दू में लिखा गया है और उर्दू पढ़ने वाले विभाग के पास कोई नहीं है, ऐसे में दिक्कत हो रही है। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने सदन में ये मामला उठाया जिस पर राकेश कालिया, केवल पठानिया और विनोद सुल्तानपुरी ने भी अनुपूरक सवाल उठाए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने माना कि राजस्व रिकॉर्ड उर्दू में लिखा गया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उर्दू पढ़ने के लिए विभाग खुद किसी को बुलाए ताकि लोगों को पैसा न देना पड़े।

चर्चा

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सरकार राज्य में डैम सेफ्टी एक्ट को कड़ाई से लागू करेगी, ताकि प्रदेश में बीबीएमबी जैसे संस्थान बांधों से अचानक पानी छोड़कर प्रदेश को तबाह न कर सके। विधानसभा में आज राज्य में आपदा को लेकर हुई चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने राज्य में पिछले वर्ष और इस वर्ष आई आपदा में अब तक का सबसे बेहतरीन काम किया है और सबसे कम समय में लोगों तक राहत पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि सरकार एसडीआरएफ को और मजबूत करेगी और पंचायतों में आपदा मित्र रखने के अलावा लोगों को आपदा के प्रति प्रशिक्षित किया जाएगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने का प्रयास कर रही है, ताकि लोगों को समय पर बेहतर सुविधा मिल सके। जगत सिंह नेगी ने इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ राजनीतिक आपदा लाने का भी प्रयास किया। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश के आपदा प्रबंधन कानून के तहत केंद्र से जो भी पैसा मिला है, वह कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ही वर्ष 2005 में यह कानून बनाया था और इसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं है। इससे पूर्व, चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आपदा से सड़कों को भारी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार आई आपदा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया है और रिकार्ड 15 दिनों के भीतर तीन बैली पुल लगाए। विधायक संजय रत्न, सुरेश कुमार, अजय सोलंकी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया।

वॉकआउट

प्रदेश विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच मॉनसून सत्र के दौरान चल रहा गतिरोध आज भी जारी रहा। विपक्षी दल भाजपा ने सदन में भारी हंगामा किया और बाद में पूरा विपक्ष सदन से वाकआउट कर चला गया। सदन की बैठक आरंभ होते ही भाजपा के विपिन सिंह परमार ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से प्वाइंट आफ आर्डर के माध्यम से अपना मुद्दा उठाने की अनुमति मांगी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें यह अनुमति नहीं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि विपक्ष प्रश्नकाल के बाद ये मुद्दा उठा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष की इस व्यवस्था से विपिन सिंह परमार संतुष्ट नहीं हुए और अनुमति न मिलने पर पूरा विपक्ष अपनी सीटों पर खड़ा हो गया और शोरगुल करने लगा। बाद में पूरा विपक्ष सदन से नारेबाजी करते हुए बाहर चला गया। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के हंगामे और वाकआउट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वास्तव में विपक्ष में आपसी लड़ाई बहुत बढ़ गई है। इसलिए उसके सभी नेता तनाव में हैं और वह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र से पहले ही यह तय हो गया था कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले हर मुद्दे का जवाब देगी। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन

चौहान ने विपक्षी दल भाजपा द्वारा सदन में किए गए हंगामे और वाकआउट को दिवालियापन करार देते हुए कहा कि विपक्ष को जनता की फिक्र नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भाजपा का वाकआउट राजनीतिक ड्रामा है और सदन इसकी निंदा करता है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्ष के हंगामे और वाकआउट पर कहा कि सदन के भीतर कार्यवाही नियमों के तहत ही चलेगी।

ज्ञापन

इस बीच विपक्षी दल भाजपा ने प्रदेश के वित्तीय हालात और विधानसभा अध्यक्ष के रवैये को लेकर आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का व्यवहार सदन के अंदर और बाहर जहां विधायकों की भावनाओं को आहत कर रहा है वहीं अध्यक्ष के संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों और परंपराओं के खिलाफ काम करते हुए सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज सुबह भी भाजपा विधायक दल द्वारा नियम 2 सौ 74 के तहत विधानसभा सचिव को अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प प्रस्तुत करने के बावजूद सत्र शुरू होने पर अध्यक्ष अपने आसन पर आकर बैठ गए, जबकि नैतिकता के आधार पर उन्हें संकल्प पेश होने, उस पर चर्चा और मतदान होने तक आसन पर नहीं आना चाहिए था। उन्होंने राज्यपाल को बताया नियम 67 के तहत प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों, विशेषकर आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्यपाल से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया।

बधाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर निषाद कुमार को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने पैरालंपिक में लगातार रजत पदक जीतने के लिए उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी निषाद कुमार को ऊंची कूद में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के लोगों के लिए यह गर्व की बात है कि प्रदेश के युवा ने इस खेल में अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पदक जीता है। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निषाद कुमार की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। अग्निहोत्री ने कहा है कि निषाद कुमार ने ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीत कर देश व प्रदेश को गौरवान्वित किया है। निषाद कुमार ऊना ज़िले की अब तहसील के बदाऊं गांव के रहने वाले हैं। निषाद कुमार की इस उपलब्धि पर उनके परिजनों सहित ज़िले में भी खुशी की लहर है।

हड़ताल

आई.जी.एम.सी. शिमला में रोगी कल्याण समिति आर.के.एस. के 55 कर्मचारी आज से पूरे दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। नियमित पे-स्केल की मांग पूरी न होने के कारण इन कर्मचारियों में रोष है। आर.के.एस. कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आज आई.जी.एम.सी में सैंकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष अरविंद पाल ने बताया कि जब तक सरकार द्वारा उनकी नियमित पे-स्केल की मांग को पूरा नहीं किया जाता, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी।